

एनजीटी ने अवैध कोयला खदान विस्फोट पर लिया स्वतः संज्ञान

नई दिल्ली, एजेंसी।

एक अंग्रेजी अखबार में छह फरवरी को छपी 'मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाके से 18 की मौत' शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने पर्यावरण कानूनों के निरंतर उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त है। यह चिंता तब व्यक्त की गयी है जब एनजीटी ने 'रेट-होल' कोयला खदान पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा है और इस प्रतिबंध को उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। अधिकरण ने मंगलवार को टिप्पणी किया कि मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में अवैध रूप से संचालित 'रेट-होल' कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट के कारण हुई।

यह घटना प्रथम दृष्टया में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के उल्लंघन का संकेत देती है। अधिकरण ने इन आरोपों पर भी गौर किया कि मौजूदा निगरानी तंत्र के बावजूद प्रभावशाली व्यक्तियों के संरक्षण में अवैध खनन गतिविधियां लगातार जारी हैं। इस मामले पर अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ ए सेंथिल वेल की पीठ ने विचार किया।

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर उभरा विवाद

हुसेन ने दावा किया कि विधायक दल में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में मजबूत आवाज उठ रही है

बेंगलुरु, एजेंसी।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर उस समय सामने आ गयी जब पार्टी विधायक इकबाल हुसेन ने कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमेया के बयान पर आपत्ति जताते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का अवसर देने की मांग दोहरायी। हुसेन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सिद्धारमेया के पुत्र श्री यतींद्र के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमेया को

पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी है। हुसेन ने कहा कि इस तरह के बयान पार्टी अनुशासन के खिलाफ हैं और नेतृत्व को असहज स्थिति में डालते हैं। उन्होंने कहा, हम एक अनुशासित पार्टी हैं और हमें उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। बार-बार अपने पिता के समर्थन में बोलना और हाईकमान को असहज करना उचित नहीं है। हुसेन ने श्री यतींद्र को सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने की सलाह दी। हुसेन ने दावा किया कि विधायक दल में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में मजबूत आवाज उठ रही



है। उनके अनुसार 80 से 90 कांग्रेस विधायकों ने शिवकुमार के नाम को सिफारिश पार्टी हाईकमान से की है। उन्होंने कहा, हमने फैसला

विधायक भ्रम की स्थिति से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से चुप हैं, लेकिन निजी तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हुसेन ने यह भी कहा कि निजी संबंधों का असर राजनीतिक फैसलों पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर पीढ़ी अपने बेटे से और हर बेटा अपने पिता से प्रेम करता है, लेकिन राजनीति में अनुशासन जरूरी है। विधायक ने स्पष्ट किया कि सरकार के गठन के पहले दिन से ही वह श्री शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि श्री शिवकुमार को इसी कार्यकाल में अवसर मिले। कांग्रेस एमएलसी

चन्नराजा हत्तिहोली ने भी श्री शिवकुमार को नेतृत्व का मौका दिए जाने का समर्थन किया। नवंबर 2025 से ही कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें जारी हैं, जब सिद्धारमेया सरकार अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के मध्य बिंदु के करीब पहुंची थी। श्री सिद्धारमेया और श्री शिवकुमार के अलावा गृह मंत्री जी. परमेश्वर को भी संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पिछले सप्ताह यतींद्र सिद्धारमेया ने कथित तौर पर कहा था कि हाईकमान ने श्रीमती पवार को पूरा कार्यकाल जारी रखने की अनुमति दे दी है।

एक नजर

मिजोरम का बजट 26 फरवरी को पेश होगा

आइजोल, एजेंसी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा 2026-27 वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट 26 फरवरी को विधानसभा में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री लालदुहोमा वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष लालबियाकजामा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमिटी (बीएसी) की दूसरी बैठक में तय किया गया।

पहले 5 फरवरी की बैठक में बजट पेश करने की तारीख 19 फरवरी निर्धारित की गई थी। लेकिन विचार विभाग की तैयारियां पूरी न होने के संकेत के बाद तारीख में बदलाव किया गया। सत्र पहले 12 मार्च को समाप्त होना था, लेकिन अब इसे चार दिन बढ़ाकर 16 मार्च तक कर दिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह 17 फरवरी को नौवीं मिजोरम विधानसभा के छठे सत्र के उद्घाटन दिवस पर अभिभाषण देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 18 फरवरी को लिया जाएगा और उसी दिन इसके पुरा होने की संभावना है।

प्रियांका खरवट ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियांका खरवट ने मंगलवार को विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की कड़ी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि उनके विचार में जिसने 'भारत के खिलाफ काम किया' वह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का हकदार नहीं है। खरवट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए इस मांग की आलोचना के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया।

उन्होंने सवाल किया कि अंग्रेजों से बार-बार माफी मांगने वाले श्री सावरकर को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों सम्मानित किया जाना चाहिए। मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल का जिक्र करते हुए कहा कि हालांकि दशकों तक हजारों स्वतंत्रता सेनानी वहां कैद रहे लेकिन केवल कुछ ही लोगों ने दया याचिकाएं दायर कीं और श्री सावरकर ने सबसे अधिक याचिकाएं दायर की थीं।

लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष एवं स्वस्थ संवाद जरूरी: पायलट

टोंक, एजेंसी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष एवं स्वस्थ संवाद जरूरी बताते हुए कहा है कि मजबूत विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है लेकिन आज जो टकराव एवं दमन की राजनीति उत्पन्न हो गई है, यह लोकतंत्र में सही नहीं है। पायलट मंगलवार को यहां अपने पिता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती पर श्री भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति के सहयोग से टोंक में आयोजित 'निःशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर' के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन आज चुनाव लड़ना,



प्रतिस्पर्धा होना नफरत में तब्दील होता जा रहा है। एक-दूसरे में प्रति राजनीति में जो घुणा एवं तनाव पैदा हो गया है, वो कोई शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र में यदि सब दुश्मन बन जायेंगे तो सहमति कैसे बनेगी। उन्होंने कहा कि आज जो संसद में हो रहा है, इससे सभी भली-भांति परिचित है। हमारे लोकतंत्र की परम्परा रही है कि आलोचना करना, आईना दिखाना, सवाल पूछना,

शहरी निकायों की मूलभूत जरूरतों पर रहेगा फोकस: उत्तम कुमार रेड्डी

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना के सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार शहरी स्थानीय निकायों की मूलभूत सामुदायिक जरूरतों को प्राथमिकता देगी। रेड्डी ने बुधवार को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए एक सप्ताह तक चले अपने व्यापक प्रचार अभियान का समापन किया। इस दौरान उन्होंने सूर्यापेट जिले और निजामाबाद संसदीय क्षेत्र के विभिन्न शहरी निकायों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना की एक-तिहाई से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

आंध्र प्रदेश को अग्रणी कृषि मॉडल बनाने पर सहमति

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान आंध्र प्रदेश को देश का एक अग्रणी कृषि-विकास मॉडल बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'वैल्यू चेन' (मूल्य श्रृंखला) विकसित करने पर सहमति बनी। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने 'विकसित भारत जी-राम-जी' योजना के लिए सबसे पहले बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री नायडू को बधाई देते हुए इसे एक दूरदर्शी पहल बताया।

आंध्र प्रदेश को अग्रणी कृषि मॉडल बनाने पर सहमति

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान आंध्र प्रदेश को देश का एक अग्रणी कृषि-विकास मॉडल बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'वैल्यू चेन' (मूल्य श्रृंखला) विकसित करने पर सहमति बनी। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने 'विकसित भारत जी-राम-जी' योजना के लिए सबसे पहले बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री नायडू को बधाई देते हुए इसे एक दूरदर्शी पहल बताया।

सुनेत्रा पवार ने संभाला महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री का पदभार

मुंबई, एजेंसी।

श्रीमती सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को मुंबई स्थित मंत्रालय में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया। वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं हैं। 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में उनके पति एवं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद 31 जनवरी को उन्हें पद की शपथ दिलायी गयी थी। पदभार ग्रहण करते समय उनके साथ पुत्र पार्थ पवार, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, श्री सुनील तटकरे, श्री छगन भुजबल सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। अपने पहले आधिकारिक दिन की शुरुआत श्रीमती सुनेत्रा पवार ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा-

अर्चना कर की। इसके बाद उन्होंने मध्य मुंबई के दादर स्थित चैत्यभूमि पहुंचकर भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संविधान निर्माता की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित कर कुछ क्षण मौन भी रखा। वह बाद में मुंबई स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) कार्यालय पहुंचीं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पति अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। समर्थकों ने नारे लगाकर उनके प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में श्रीमती पवार को राज्य उत्पाद शुल्क, खेल और अल्पसंख्यक विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चंद्रबाबू ने पाटिल से पोलावरम परियोजना पर रोक को रद्द करने का किया आग्रह

नई दिल्ली, एजेंसी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और उनसे पोलावरम परियोजना पर लगाए गए कार्य निषेध आदेश को स्थायी रूप से यह कहते हुए रद्द करने का अनुरोध किया कि इससे परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ये परियोजनाएं राज्य के हितों की रक्षा करने, किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने और आंध्र प्रदेश के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता एवं अंतरराज्यीय नदी जल



विवादों के समाधान से संबंधित लिखित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पोलावरम की दार्हिनी एवं बाईं ओर की मुख्य नहरों की क्षमता बढ़ाने के कारण हितों की रक्षा करने, किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने और आंध्र प्रदेश के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

चरण के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पोलावरम-नल्लामाला सागर लिंक परियोजना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य गोदावरी नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की

आर मोड़ना है। उन्होंने इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण जीवन रेषा बताया जो पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी और राष्ट्रीय नदी लिंकन नीति के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ-साथ अनुमोदन का अनुरोध किया।

राजनीति सदन को गुमराह करने के मामले में उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा विधायक से मांगा इस्तीफा

उमर ने भाजपा विधायक के 'रोपवे' 'मंजूरी आरोप को किया खारिज

सतीश वर्मा

परियोजना को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भाजपा विधायक बलदेव शर्मा पर तीखे विवाद फिलहाल थमता दिखाई नहीं देता है। जम्मू से विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान श्री माता वेण्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलदेव राज शर्मा ने कहा था कि इस परियोजना को उमर अब्दुल्ला सरकार में मंजूरी दी। इसके बाद आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बयान दिया कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड चेक किए हैं, जोड़े, पिट्टू-पालकी वालों से लेकर कटरा बाजार के कारोबारी भी एक अरसे से प्रबल विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस रोपवे के बन जाने से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा और उनका जीवन दूधर हो जाएगा। जबकि



इस विधानसभा क्षेत्र, श्री माता वेण्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव राज शर्मा का कहना है कि इस परियोजना के मद्देनजर केवल कटरा अथवा जम्मू को ना देखा जाए बल्कि श्री मां वेण्णो देवी का तीर्थ स्थल देश भर के श्रद्धालुओं के लिए है। विकलांग तथा बुजुर्ग जो चल नहीं पाते, उनकी सुविधा के लिए परियोजना को अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री माता

वेण्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 'रोप वे' के कारण प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लिए पुनर्वास का भरोसा दिया है। उपराज्यपाल द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने हित धारकों से बातचीत करके उनकी चिंताओं का निवारण किया है। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के खिलाफ आंदोलन चला रहे लोगों की ओर से उन्हें जान से मारने तथा संपत्ति को जलाने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनके साथ ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जिम्मेदार होंगे। बल्कि उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनुमति के बिना 'रोप वे' विस्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष का रूप

मुख्यमंत्री कटरा के आंदोलनकारी को विनोद प्रदर्शनों के लिए भड़का रहे हैं। भाजपा विधायक बलदेव राज शर्मा ने यहां विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए 14 अगस्त 2025 के उस आदेश को पढ़कर सुनाया, जिसमें सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए मंजूरी दी गई थी। इस पर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन को बताया कि जब उन्होंने इस बाबत रिकॉर्ड खंगाले तो यह साफ हो गया कि सितंबर 2024 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से सदन उक्त प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्होंने मंजूरी दी थी। यह मंजूरी उनकी सरकार गठन से एक माह पहले दी गई थी और सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है।

उत्तर रेलवे खुली निविदा सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से बहिष्कृत मंडल अभियंता / प्रबन्ध, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई-टेंडर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।	
1. कार्य का नाम : सहायक मंडल अभियंता / पानीपत के अंतर्गत एसएसई / डब्ल्यू / पानीपत खंड में SFDE रेलवेगन पर वस्तुओं के गोदाम, व्यापारी कक्ष, श्रमिक कक्ष, घुंघरू मार्ग और परिचरणीय क्षेत्र में सुचारु और अन्य विधियां	
2. अनुमानित खर्च : ₹. 2,85,46,043.55/-	
3. ब्यौरे हर साई : ₹. 2,92,700/-	
बयाना राशि केवल बैंकिंग या भुगतान गेटवे के रूप में होनी चाहिए।	
नोट :- एक,डीआर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ई.पम.डी, स्वीकार नहीं की जाएगी। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/सीई-1 /सीटी/5/1 दिनांक 31/08/2016 के अनुसार आई.आई.पी.एस. पर आमंत्रित निविदा के लिए।	
4. समापन अवधि : 12 नहीने	
5. ई-निविदा खोलने और प्रस्तुत करने के लिए दिनांक और समय	06.03.2026 को 15:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने का समय दिनांक 06.03.2026 को 15:00 बजे।
6. निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रश्न खरीदा जा सकता है।	www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
7. सामान्य प्रकर के कार्य के लिए काम के अलावा कोई भी स्थिति कार्य।	
नोट :- शपथ पत्र संलग्नक-XXIV अनिवार्य रूप से रूप में निविदा शर्तों के साथ संलग्न नए प्राकृत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और सभी संलग्नक दस्तावेज निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना चाहिए। पत्र संख्या :- 128-डब्ल्यू/280/निविदा सूचना /25-26/डब्ल्यू-1 (NIT-45) दिनांक :- 09.02.2026	446/2026

Nidhi Services Limited

Regd. Off : 5/19-B, Roop Nagar, Delhi - 110007

Tel.: 011-43215145, Mobile: 09811021216

CIN: L65999DL1984PLC018077

E-mail: nidhiservicesltd@gmail.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2025

Pursuant to Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of Nidhi Services Limited ('the Company') at its meeting held on 09th February, 2026 has approved the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2025 along with Limited review report issued by the Statutory Auditors of the Company.

The aforementioned financial results along with the Limited review report of the Statutory Auditors thereon are available on

www.nidhiservicesltd.com and the said financial results can also be accessed by scanning a Quick Response (QR) code given below:



For Nidhi Services Limited
Sd/-
Udit Agarwal
Whole Time Director
Place: Delhi
Date: 09th February, 2026
DIN: 00239114